(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्हें अप्रैल, 91 से 31 दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में 578 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । केन्द्रीय भंडार ने सूचित किया है कि उन्हें इस अवधि के दौरान सुपर बाजार की तुलना में ऊंचे मूल्य अथवा घटिया किस्म के बारे में ग्राहकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री मूल्यों में प्रायः दोनों और अंतर देखा गया है । सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार दो अलग-अलग सहकारी संगठन हैं, जिनके अधिप्राप्ति के स्रोत, अधिप्राप्ति के समय तथा लाभ के मार्जिन और अन्य लागतें अलग-अलग हैं । तथापि, दोनों संगठनों के खुदरा मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य से नीचे नियत किए जाते है ।

(घ) और (ङ) सुपर बाजार को आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की बारीकी से मानीटरिंग करने की सलाह दी गई है ।

दिल्ली में राशन की वस्तुओं के वितरण के लिए नई योजना

4249. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन की वस्तुओं के वितरण और उनकी उपलब्धता के संबंध में एक नई योजना तैयार की जा रही है या किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यह नई योजना वर्तमान योजना में किन-किन मामलों में अलग होगी;

(घ) इस योजना से किस प्रकार का सुधार सुनिश्चित किया जायेगा ?

(ङ) क्या इस संबंध में जनमत सहित सभी पहलुओं पर विचार किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि सरकार भारतीय खाद्य निगम से चीनी के वितरण का कार्य लेकर लेवी चीनी के वितरण का कार्य तीन नामित अभिकरणों, अर्थात् दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार को 50:30:20 के अनुपात में सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । ये अभिकरण लेवी चीनी सीधे मिलों से उठाएंगे और उसे उचित दर की दुकानों में वितरित करने की व्यवस्था करेंगे ।

(ग) और (घ) इस समय दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों से चीनी उठाता है और दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित उचित दर की दुकानों को उसकी आपूर्ति की व्यवस्था करता है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित परिवर्तन से उचित दर की दुकानों को अच्छी किस्म की चीनी की समय से आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी ।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्ताव के ब्यौरे को सभी संबंधितों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

Research Studies on PDS

4250. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether any Research Studies have been conducted by Government on various aspects of Public Distribution System which have been printed and made available to the general public ; and

(b) what are the major findings of the Research Studies on the effectiveness of Public Distribution System in Kerala ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) The Programme Evaluation Organisation (PEO) of the Planning Commission published an "Evaluation Report of the Essential Supplies Programme" in February, 1985. The National Sample Survey Organisation conducted a study on the "Utilisation of Public Distribution System" in the forty second round of the National Sample Survey during July, 1986 to June, 1987. These reports have been published.

(b) An evaluation of the PDS in Kerala was sponsored by the Government in 1987 and was carried out by the Centre for Management Development, Thiruananthapuram. The report concluded that though PDS in Kerala is effective and consumers have favourable disposition towards PDS, there is scope for making the PDS more effective by evercoming the shortages/deficiencies such as unprofitable operations of fair price shops, malpractices by fair price shops and declining involvement of Co-operative sector in the PDS. This study report has not been published.

Persons detained under PBMMSEC Act, 1980

4251. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) how many persons have been detained under the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 in States during 1992-93 and 1993-94 ;

(b) whether Government have conducted any study about the implementation of the Act ; and

(c) if so, what are the findings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Calender year-wise information is listed below :—

Year	No. of detention
1972 . . .	172
1973 . . .	132
1994 . . .	22
(Up to 31-3-94)	

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सप्लाई की जा रही वस्तुओं का विक्रय मूल्य

4252. **श्री राघवजी** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रति क्विंटल विक्रय मूल्य क्या था और खरीद के लिए उनका समर्थन मूल्य क्या क्या था और प्रति वर्ष प्रति क्विंटल कितनी राज सहायता दी गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वस्तु का प्रति वर्ष कितनी मात्रा में वितरण किया गया और प्रत्येक वस्तु कतनी-कितनी मात्रा में घटी और उसके क्या कारण थे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल, गेंहू, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल और सॉफ्ट कोक के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नवत् हैं :—

(रु० प्रति क्विंटल)

वस्तु	सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लागू	कॉमन	फाइन	सुपर फाइन
1	2	3	4	5
चावल	28-12-91	377	437	458
	11-1-93	437	497	518
	1-2-94	537	617	648
गेहूं	28-12-91	280		
	11-1-93	330		
	1-2-94	402		